₹ 5

वर्ष 10, अंक -31, 03 से 09 फरवरी, 2025, जमशेदपुर

RNI No.: JHAHIN/2014/63781

https://epaper.rashtrasamvad.com

www.rashtrasamvad.com

राष्ट्र संवाद

आपका राष्ट्र आपका संवाद : साप्ताहिक समाचार पत्र

महाकुंभ में मची भगदड़

राष्ट्र संवाद समूह की
रजत जयंती वर्ष समापन सह
स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई

डॉ.जटाशंकर पांडे

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
सह संस्थापक नारायण प्राइवेट आईटीआई
लुपुंगडीह, नीमडीह, सरायकेला खरसावां ,झारखंड

नजरिया

महाकुंभ भगदड़ में मौतों का जिम्मेदार कौन ?

देवानंद सिंह

महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इस दुखद हादसे से यह सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मजे की बात यह है कि यह हादसा ऐसी स्थिति में हुआ, जब सरकार के पास लाखों लोगों के पहुंचने की जानकारी थी, जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क था, लेकिन फिर भी यह हादसा कैसे हो गया? क्या प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा के अभाव या भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता इसके कारण बने? ऐसे मौकों पर राजनीतिक दल हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती हैं, वो केवल एक-दूसरे को घेरने का प्रयास करती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सुरक्षा प्रबंधों में ढील और असंवेदनशीलता ने इस भयावह हादसे को जन्म दिया। ऐसे में, समय रहते सुधार और जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो ऐसे हादसे और घट सकते हैं। यदि, प्रशासन ने समय रहते भीड़ प्रबंधन, रास्तों का सही ढंग से विभाजन और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने जैसे पर्याप्त इंतजाम किए होते तो इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता था। एंट्री पइंट्स की बंदी, भीड़ को नियंत्रित करने की सही योजना और सुसंगत मार्गदर्शन के अभाव में यह दुर्घटना हुई। क्या प्रशासन ने भगदड़ के संभावित खतरे को गंभीरता से लिया था? क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय और पुलिस बल की तैनाती की गई थी? इन सवालों के उत्तर प्रशासन को देने होंगे। धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा के प्रबंधों में कई बार ढिलाई देखने को मिलती है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में, जहां हर दिन लाखों लोग एकत्र हो रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसके बावजूद अक्सर यह देखा गया है कि धार्मिक आयोजनों के आयोजक और प्रशासन, श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा के मामलों में लापरवाह होते हैं। जब एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं, तो एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे न केवल धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं, बल्कि व्यवसाय, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं का भी भारी लाभ होता है, लेकिन जब सुरक्षा की कमी होती है या प्रशासन की उपेक्षा होती है तो इस तरह के हादसों के कारण पूरा आयोजन सवालों के घेरे में आ जाता है। क्या प्रशासन ने केवल आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सुरक्षा प्राथमिकता होती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।

प्रयागराज भगदड़: प्रशासनिक लापरवाही या भक्तों का उन्माद

प्रियंका सौरभ

प्रयागराज में हुई भगदड़ के बारे में सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई। यह घटना निस्संदेह विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक चर्चाओं को जन्म देगी। विपक्ष आलोचना करेगा, जबकि सरकार अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करेगी, लेकिन जो लोग मर चुके हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रयागराज में संगम तट पर वर्ष 2013 के कुंभ मेले के दौरान 10 फरवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या का स्नान था। कुचलने और गिरने से 35 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। जिनका अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चला था। 1954 में मौनी अमावस्या के दिन नेहरू जी ने संगम में स्नान किया, जो इस मेले का मुख्य आकर्षण था। इस कुंभ मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। मौनी अमावस्या के स्नान के समय, एक हाथी नियंत्रण से बाहर हो गया और भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में करीब 500 लोग मारे गए।

भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने और सूचना देने के लिए लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, रात के समय मेले में रोशनी के लिए 1000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थीं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद, कुंभ मेले में हाथियों के उपयोग पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। अपने घर में छोटा-सा कार्यक्रम करिए उसको सकुशल संपन्न कराने में हवा निकल जाती है यहाँ तो पूरा विश्व आया हुआ है करोड़ों की संख्या में। एक पौराणिक शहर की सीमाओं पर विचार करना चाहिए, जिसे अपनी धार्मिक विरासत को बनाए रखते हुए आठ करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। दस लोगों के लिए डिजाइन की गई जगह में सौ लोग कैसे रह सकते हैं? यह विचार करने के लिए एक महवपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा, वीवीआईपी संस्ति और सरकार के मुनाफे की खोज, जिसमें राजस्व के लिए हर उपलब्ध भूमि को पट्टे पर देना और बिचौलियों को शामिल करना शामिल है, के बीच का सम्बंध मामले को और जटिल बनाता है। यह धार्मिक भक्ति का मामला है, प्रतिस्पर्धा या उन्माद का नहीं। कुछ लोग इसे प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं। लिखना और आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन जहाँ पर लाखों, करोड़ों लोगों की भीड़ हो ओर उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग हो। घाटों पर जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके बाहर निकल रहे हो और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने जा रहे हों। हादसे की संभावना बनी रहती है और अफसोस हादसा हो ही गया। हमेशा याद रखें। प्रशासन एक-एक का हाथ पड़कर स्नान नहीं करवा सकता। हादसा कहीं भी हो सकता है। ना इसमें पूरा प्रशासन का दोष है और ना ही इसे विपक्ष की साजिश कहा जा सकता है। यह महज एक हादसा है। हादसे के बाद पूरे संगम क्षेत्र में स्थिति बिलकुल सामान्य है लेकिन मीडिया अपने टीआरपी के लिए सनसनी पैदा कर रहा है। जबकि मीडिया की जिम्मेवारी है कि वह घटना (भगदड़) की वजह की रिपोर्टिंग पर करें। इसके अतिरिक्त लोग महाकुम्भ में जिस श्रद्धा आस्था के साथ आएँ हैं, उसी श्रद्धा पूर्वक उन्हें कर्तव्यबोध भी रहे। सरकार के नियम, अनुशासन, चेतावनी का उसी आस्था से पालन करे। जब अयोध्या और काशी में आशातीत भीड़ हो गई है तो प्रयागराज में महाकुंभ में सम्मिलित श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। सभी लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान के लिए हठ न करें, चालीस किलोमीटर इधर और उधर, यानी अस्सी किलोमीटर तक फैला हुआ स्नान घाट बनाया गया है। वहीं स्नान कर पया व्यवस्था में सहयोग बनाएँ।

ऐसा लगता है कि सरकार खुद को सर्वश्रेष्ठ आयोजक के रूप में दिखाने पर केंद्रित है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन को बढ़ावा देने में अधिक रुचि रखते हैं, आम भक्तों की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं। ब्रह्म कल्प के दौरान लगभग 45 दिनों तक, शाही स्नान (शाही स्नान) प्रतिदिन होता है, फिर भी हमारे धार्मिक नेताओं ने इसे श्रद्धालुओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँचाया है। इन नेताओं द्वारा कुंभ स्नान का वास्तविक महव जनता को पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया है। यदि सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए अक्सर टेलीविजन पर आने वाले धार्मिक व्यक्ति कल्पवास के इन 45 दिनों के दौरान प्रत्येक प्रहर के दौरान स्नान के महव पर जोर देते, तो भारी भीड़ को अलग-अलग दिनों में फैलाया जा सकता था, जिससे संभावित रूप से ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता था। अत्यधिक प्रचार के कारण महाकुंभ में बेहिसाब भीड़ जमा हो गई। इसके अतिरिक्त वीआईपी यानी अति विशिष्ट को जरूरत से ज़्यादा महव और आमजन को अनेक रास्तों पर रोकना या वापस भेजना या मोक्ष मार्ग पर अति विशिष्ट के लिए अलग मार्ग भी एक कारण। भगदड़ के लिए बस एक छोटीसी गलती की जरूरत होती है। एक बात और असरदार या धनी लोग द्वारा अपने पैसों के दम पर सामान्य तीर्थयात्रियों का हक मार लेना, उनको पीछे धकेल देना।

संपादकीय

12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने से बढ़ी चुनावी लाभ की संभावना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट ने वैसे तो कई पहलुओं को छुआ है, लेकिन इस बार सबसे अधिक चर्चा मध्यम वर्ग की लेकर हो रही है, क्योंकि इस बार टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर यह बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय नागरिकों, खासकर मध्यम वर्ग और युवाओं पर पड़ने की संभावना पड़ना है, इसे सरकार ने ष्आम आदमी के सपनों को पूरा करने वालाष् कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को विकसित भारत के मिशन के रूप में पेश किया है, जो देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। टैक्स फ्री आय की सीमा को 12 लाख रुपए तक बढ़ाना, खासकर सैलरीड क्लास के लिए 12 लाख 75 हजार रुपए तक बढ़ाई गई सीमा, इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आम नागरिक अपने खर्चों को बढ़ा सकें, जिससे घरेलू मांग और खपत में वृद्धि हो सके, जो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। हालांकि, यह निर्णय अर्थव्यवस्था को जल्द ही बड़ी गति नहीं दे सकता, लेकिन यह सियासी लाभ जरूर दे सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, जहां बड़े संख्या में वेतनभोगी वर्ग के लोग हैं, इस कदम से भाजपा को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आगामी चुनावों के संदर्भ में यह एक अहम कदम हो सकता है। नई टैक्स नीति में बदलाव का सबसे बड़ा पहलू यह है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, करीब 25 करोड़ लोग, जो मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हैं, सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। यह कदम उन लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिन्हें बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि, विशेषज्ञ इस फैसले से आम आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केवल एक छोटे वर्ग को राहत देगा। यह टैक्स कटौती उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा दे सकती है, खासकर उन वर्गों में जो खाद्य महंगाई से जूझ रहे हैं। जब उपभोक्ताओं के पास अधिक पैसा होगा, तो वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे कंज्यूमर कंपनियों को फायदा हो सकता है, हालांकि, मूडीज रेटिंग्स जैसे संस्थान इसके असर को लेकर अधिक आश्वस्त नहीं हैं और मानते हैं कि यह कदम सिर्फ थोड़े समय के लिए प्रभावी हो सकता है, जबकि दीर्घकालिक परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति में इस समय सुस्ती देखने को मिल रही है और जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान है। सरकार का कहना है कि अगर, भारत को 5 ट्रिलियन डलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो इसके लिए जीडीपी वृद्धि की दर 8: से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में, सरकार का यह कदम, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करना, भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नई टैक्स नीति में पुराने टैक्स रिजीम का जिक्र तक नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार का उद्देश्य अब बचत को बढ़ावा देने की बजाय उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जब लोग अधिक खर्च करेंगे, तो इससे उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होगी। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कुछ राज्यों का उल्लेख किया, जिनमें सबसे अधिक बिहार का नाम लिया गया। ○

देवानंद सिंह

> बजट में विभिन्न उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई जा सकती है, जिससे लजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके।

क्या बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ?

यह बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय होगा क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। मोदी के विजन में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी ....

ललित गर्ग

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार अपना आठवां बजट पेश किया। यह केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण वित्तीय बजट होगा। इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, इस बजट की घोषणाओं से भविष्य में राष्ट्र किन दिशाओं में आगे बढ़ेगा, उसकी मंशा एवं दिशा अवश्य स्पष्ट होगी। टैक्सपेयर्स भी इस बार वित्तमंत्री से इनकम टैक्स में राहत देने की उम्मीद कर रहा है। मिडिल-क्लास और वेतनभोगियों को भी राहत की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से यह बजट दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला होगा। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी की गारंटियों पर बल दिया जायेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति दी जायेगी। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा।

आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। बजट, शिक्षा, रक्षा, उद्योग, महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए सुधारों और प्रोत्साहनों का खाका तैयार करेगा। वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर स्लैब में बदलाव करेंगी, जिससे वेतनभोगियों एवं करदाताओं को राहत मिलेगी। इस समय वेतनभोगी एवं करदाता की 15 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपये की आमदनी पर 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर रही है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। केंद्र सरकार बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल बनाएगा। इसके अलावा, सरकार इस बार के बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर सकती है। इसमें शेयरों से मिलने वाले लाभांश, ब्याज से होने वाली कमाई और पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगाया जा सकता है।

यह बजट न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की भी संभावनाएं हैं। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा सकती हैं। आम आदमी के लिए सबसे पीड़ादायक टैक्स का बोझ है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे टैक्स का फैसला समय-समय पर जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है, लेकिन सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन शुल्कों को और तर्कसंगत बनाकर आम लोगों को कुछ राहत दे। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोजगार के अवसरों को भी कम किया है जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से खघसकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली तिमाहियों में कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन ने भी इन हालात को मुश्किल बनाया है। जिससे नौकरी चाहने वाले युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

जमशेदपुर

सरकार मदद करे तो प्रशांत जीत सकते हैं मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया का खिताब

आनंद सिंह

प्रशांत कुमार सिंह को सरकारी खर्च चाहिए. उनका लक्ष्य है मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया का खिताब जीतना. वह मानते हैं कि अब जिम का खर्च बढ़ गया है. वह जितना कमाते हैं, सब उनकी डाइट और एक्सरसाइज में ही चला गया है. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश का नाम रौशन करने के लिए वह एनजीओ की भी मदद चाहते हैं.

कौन हैं प्रशांत कुमार सिंह?

प्रशांत टेल्को, जमशेदपुर के निवासी हैं. वह बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में रुचि लेते रहे. 2 सितंबर 1993 को जन्मे प्रशांत शटर्पुट, डिस्कस थ्रो और रस्सीखींच में खासे रमे रहे. इन तीनों खेलों में उन्होंने अपना बेहतरीन दिया और यही वजह थी कि उन्हें लगातार कई वर्षों तक टाटा एथलेटिक मीट में प्रतिनिधित्व करते रहने का मौका भी मिला. 2021 से प्रतिनिधित्व का जो क्रम चला, वह आज तक बरकरार है.

बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए?

अपने बड़े भाई, पंकज कुमार सिंह को वह बॉडी बिल्डिंग करते देखते थे. 2015 में उन्होंने भी अपने अग्रज के साथ बॉडी बिल्डिंग शुरु कर दी. उन्हें ही अपना उस्ताद मान लिया. पिता प्रभुनाथ सिंह पहलवानी में थे. घर में कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग का माहौल रहा. टेल्को के जिम में ही प्रैक्टिस करते थे. पंकज सिंह मर्चेंट नेवी में अभी भी कार्यरत हैं और चीफ ऑफिसर के पद पर हैं. शुरुआती दिनों में उन्होंने ही कोचिंग दी. प्रशांत फिलहाल टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं और टाउन वार्डन की भूमिका निभा रहे हैं.

10 साल में क्या हासिल किया?

प्रशांत ने बॉडी बिल्डिंग में भरपूर नाम कमाया. वह 2015 में ओवरऑल मिस्टर झारखंड बने. इसके बाद 2016 में ओवरऑल मिस्टर झारखंड बने. 2017 में जूनियर मिस्टर इंडिया बने. 2017 में ओवरऑल मिस्टर झारखंड बने. 2018 में ओवरऑल मिस्टर झारखंड के खिताब पर कब्जा जमाया. 2021 में फिर से ओवरऑल मिस्टर झारखंड चुने गये. 2022 में ओवरऑल मिस्टर झारखंड रहे और 2023 में सतीश शुगर क्लासिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया. 2023 में डक्टर फ्लैक्स क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल (100 किग्रा से ऊपर के वजन में) प्राप्त किया. 2024 में एक बार फिर से उन्होंने ओवरऑल मिस्टर झारखंड का खिताब जीता. 2024 में वह आयरन मैन ऑफ झारखंड बने. 2024 में ही सीनियर मिस्टर इंडिया में पांचवां स्थान हासिल किया. 2024 में ईस्ट इंडिया ओवरऑल चौंपियन बने और 2024 में फिटएक्सपो में तृतीय स्थान (ब्राउंज मेडल) प्राप्त किया. आखिरी में, इस साल संपन्न सीनियर मिस्टर इंडिया का रनर अप रहे. इस तरह से देखें तो हर साल उन्होंने कुछ न कुछ हासिल ही किया और ओवरऑल मिस्टर झारखंड पर तो जैसे उनका ही कब्जा रहा.

खुराक क्या लेते हैं प्रशांत?

प्रशांत सुबह के नाश्ते में 12 अंडे और फल लेते हैं. दोपहर के भोजन में 300 ग्राम चिकन और राइस लेते हैं. रात के खाने में 300 ग्राम फिश और राइस का सेवन करते हैं. प्रोटीन सप्लीमेंट दो बार लेते हैं. दोनों बार जब वर्कआउट कर लेते हैं।

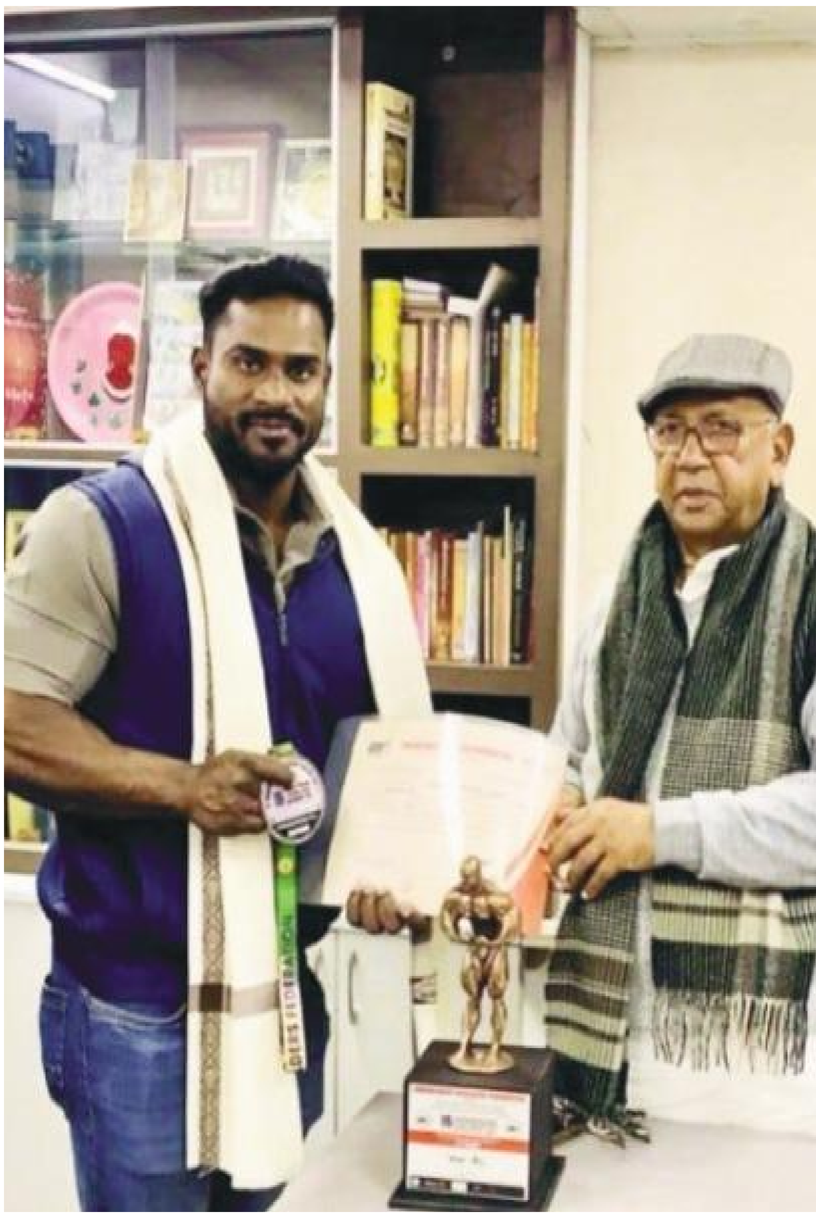

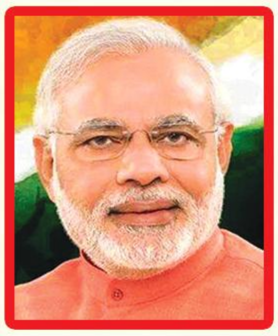

राष्ट्र संवाद समूह की
रजत जयंती वर्ष समापन सह
स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई

सबका साथ - सबका विकास

बबुआ सिंह
जिला उपाध्यक्ष भाजपा
पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

राष्ट्र संवाद समूह की
रजत जयंती वर्ष समापन सह
स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई
SRI SAI RO WATER
SHANTI NAGAR, BARIDIH BASTI,JAMSHEDPUR
PH. NO. 9234743127, 7482044449
Avilabale: 20Ltr. Jars Cool Water,
1Ltr. Water,200ml
All Party & Function

SRI SAI GAS SERVICE
SUPPLY:- 19KG COMMERCIAL LPG, OXYGEN, DA, NAITROGEN
HP GAS
N2
N2
N2
N2
N2
N2
SHANTI NAGAR, BARIDIH BASTI,JAMSHEDPUR
PH. NO. 9234743127, 7482044449

नजरिया

ग्रामीण भारत की कहानी बदल रही है स्वामित्व योजना

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) पहल से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। इस पहल के तहत सरकार द्वारा सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा और स्पष्ट स्वामित्व रिकर्ड के प्रावधान से भूमि विवादों में कमी आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण और शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम परिसंपत्तियों की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है, बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाता है, संपत्ति से सम्बंधित विवादों को कम करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कराधान और संपत्ति मूल्यांकन में सुधार करता है और पूरी तरह से गांव-स्तरीय योजना बनाने की अनुमति देता है।

डॉ सत्यवान सौरभ

स्वामित्व की आवश्यकता भारत में ग्रामीण भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का दशकों से अभाव रहा है। कई राज्यों में गांवों के आबादी क्षेत्रों के नक्शे और दस्तावेजीकरण का अभाव रहा है। आधिकारिक रिकर्ड की अनुपस्थिति के कारण, इन क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक अपने घरों को अपग्रेड करने या अपनी संपत्ति को ऋण और अन्य वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में असमर्थ थे, जिससे उनके लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो गया। इस तरह के दस्तावेजीकरण की कमी ने 70 से अधिक वर्षों तक ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में बाधा डाली। यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति रिकर्ड के महव के आलोक में एक समकालीन समाधान की आवश्यकता थी। गाँव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए, स्वामित्व योजना विकसित की गई थी। पीएम स्वामित्व ने जल्द ही खुद को इस दिशा में एक महवपूर्ण मोड़ साबित कर दिया।

पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल को स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) कहा जाता है। इसे नौ राज्यों में कार्यक्रम के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर में पेश किया गया था। यह कार्यक्रम भूमि के टुकड़ों का मानचित्रण करने और गाँव के घरेलू मालिकों को ष्अधिकारों का रिकर्डष् प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करता है। कानूनी स्वामित्व कार्ड, जिन्हें संपत्ति कार्ड या शीर्षक विलेख के रूप में भी जाना जाता है, तब संपत्ति के मालिकों को जारी किए जाते हैं, जो ग्रामीण आबादी वाले (आबादी) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।

सर्वे अफ इंडिया और सम्बंधित राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए रूपरेखा द्वारा प्रदान की गई बहु-चरणीय संपत्ति कार्ड निर्माण प्रक्रिया में पहला कच्दम है। सभी पैमानों पर राष्ट्रीय स्थलातिक डेटाबेस तैयार करने के लिए, विभिन्न पैमानों पर स्थलातिक मानचित्रण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जैसे उपग्रह इमेजरी, मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन प्लेटफर्म और हवाई फोटोग्राफी ड्रोन। समझौता ज्ञापन के पूरा होने के बाद, एक सतत संचालन संदर्भ प्रणाली स्थापित की जाती है। एक आभासी बेस स्टेशन जो लंबी दूरी की, अत्यधिक सटीक नेटवर्क आरटीके (रियल-टाइम किनेमेटिक) सुधार प्रदान करता है, संदर्भ स्टेशनों के इस नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला चरण यह निर्धारित करना है कि किन गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा और जनता को संपत्ति मानचित्रण प्रक्रिया के बारे में सूचित करना है। प्रत्येक ग्रामीण संपत्ति को चूना पत्थर (चुन्ना) से चिह्नित किया जाता है, जो गाँव के आबादी क्षेत्र (आबाद क्षेत्र) को चित्रित करता है यह जांच ध् आपत्ति प्रक्रिया का समापन है, जिसे संघर्ष ध् विवाद समाधान के रूप में भी जाना जाता है। फिर सम्पत्ति पत्रक या अंतिम संपत्ति कार्ड शीर्षक विलेख तैयार किए जाते हैं। आप इन कार्डो को खरीद सकते हैं। इस कार्यक्रम के लाभों में एक समावेशी समाज शामिल है। गांवों में कमजोर आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति संपत्ति के अधिकारों तक उनकी पहुँच के साथ सकारात्मक रूप से सहसम्बद्ध है। स्वामित्व योजना इसे संभव बनाने का प्रयास करती है। आबादी की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा की कमी के कारण भूमि-संघर्ष के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। स्थानीय स्तर पर संघर्षों के अंतर्निहित कारणों को सम्बोधित करना स्वामित्व योजना का लक्ष्य है। बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ जो उच्च-रिजल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करती हैं, सड़कों, स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं, नदियों, स्ट्रीटलाइट्स और अन्य बुनियादी ढाँचे में सुधार लाती हैं। अधिक सुलभ संसाधनों और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से। लोगों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में मुद्रीत करने में मदद करना मुख्य लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों में संपत्ति कर लगाया जाता है, वहाँ इसे सरल बनाने से निवेश को बढ़ावा मिलता है और व्यापार करना आसान हो जाता है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

भूमि स्वामित्व से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को विकास और सशक्तिकरण के अवसरों में बदलकर, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की कहानी बदल रही है। यह योजना, जिसमें डिजिटल संपत्ति कार्ड और परिष्त ड्रोन सर्वेक्षण शामिल हैं, केवल सीमाओं और नक्शों के बजाय संभावनाओं और सपनों के बारे में है। स्वामित्व सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बन गया है क्योंकि गाँव इस बदलाव का स्वागत करते हैंय यह बढ़ी हुई आजादी, ज्यादा चतुराईपूर्ण योजना और ज्यादा एकजुट, शक्तिशाली ग्रामीण भारत के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। स्वामित्व योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत बदल रहा है। भूमि स्वामित्व से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयाँ विकास और आत्मनिर्णय के अवसरों में बदल रही हैं। बाधाओं को दूर करने, विवादों को निपटाने और संपत्ति को आर्थिक उन्नति के लिए एक शक्तिशाली साधन में बदलने के लिए नवाचार और समावेशिता को जोड़ा जा रहा है। डिजिटल संपत्ति कार्ड और परिष्त ड्रोन सर्वेक्षण इस बात के दो उदाहरण हैं कि कैसे योजना सरल सीमाओं और मानचित्रों से आगे जाती है। यह अवसरों और आकांक्षाओं से भरपूर है। गाँव इस बदलाव को अपना रहे हैं और स्वामित्व महज सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता, बेहतर योजना और अधिक एकजुट ग्रामीण भारत सभी इसके द्वारा गति प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्र संवाद
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
Web site : www.rasntrasamvad.com
RNI No.: JHAHIN/2014/63781

संपादक: देवानंद सिंह
प्रबंध संपादक: रश्मि सिंह
कार्यकारी संपादक: विजय शंकर मिश्रा
समन्वयक संपादक: रत्नेश कुमार, अमन कुमार
महाप्रबंधक: धीरज कुमार सिंह
प्रभारी बिहार झारखंड: निजाम खान,
बिहार ब्यूरो प्रमुख : चन्दन कुमार शर्मा
विशेष संवाददाता: प्रकाश सिंह, जितेन्द्र शर्मा, जे पी सिंह
कार्यालय प्रभारी: ज्योति मिश्रा

राष्ट्र संवाद में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार सुरक्षित। लेखकों के मतों एवं कथनों के लिए संपादक व प्रकाशक की अनुमति अनिवार्य नहीं। सभी विवादों का निपटारा जमशेदपुर न्यायिक क्षेत्र में ही किया जायेगा। छायाचित्र एवं अन्य सामग्रियां भी अन्य पत्र-पत्रिकाओं से साभार।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक देवानंद सिंह द्वारा चंदू प्रेस, 63 पटपड़गंज इंडिस्ट्रयल एरिया, दिल्ली-92 से मुद्रित तथा अमन पब्लिकेशन राष्ट्र संवाद, 66 गोलमुरी बाजार, जमशेदपुर-3 झारखंड से प्रकाशित।
फोन: 0657-2341060
मो. : 09431179542/ 09334823893/ 07739802044